मंगलवार

06 अक्टूबर 2026

- देहरादून
- वर्ष 34
- अंक 255
- पृष्ठ 8
- मूल्य ₹ 1.00

34 साल से देहरादून का विश्वास

दूनवैलीमेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94

email: doonvalley_news@yahoo.com Website: dunvalleymail.com

डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

डंपर व स्कॉर्पियो की जबरदस्त टक्कर

एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

हमारे संवाददाता

लक्सर। लक्सर-पुरकाजी रोड पर देर रात स्कॉर्पियो और मिट्टी से भरे डंपर की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरनगर जिले का एक परिवार स्कॉर्पियो से लक्सर की श्रीराम कॉलोनी में अपने रिश्तेदार के घर आयोजित जन्मदिन समारोह में शामिल होने आया था। परिवार के सात सदस्य समारोह में शामिल होने के बाद देर रात वापस मुजफ्फरनगर लौट रहे थे। इसी दौरान लक्सर-पुरकाजी रोड पर भैंसली वाला गांव के पास उनकी स्कॉर्पियो की सामने से आ रहे डंपर से जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया।

बताया गया कि स्कॉर्पियो में सवार 50 वर्षीय आदेश, उनकी 35 वर्षीय बहन निशा, 37 वर्षीय बहन राखी और आदेश की 12 वर्षीय बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, हादसे में आदेश की पत्नी, उनकी बुजुर्ग मां और छह वर्षीय छोटी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गईं। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। घायलों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। हादसे के बाद डंपर



चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भी भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि लक्सर-पुरकाजी रोड पर मिट्टी से भरे डंपर तेज रफ्तार में दौड़ते हैं, जिससे सड़क पर दुर्घटना का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से डंपरों की रफ्तार और संचालन की निगरानी बढ़ाने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

ट्रक और पुलिस बस की जबरदस्त भिड़ंतः बस पलटी, ट्रक क्षतिग्रस्त

चार पुलिसकर्मी सहित सात लोग घायल

हमारे संवाददाता

देहरादून। मोहब्बेवाला हाईवे पर सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह करीब 8 बजे एक बार फिर ट्रक और पुलिस बस की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस बस पलट गई, जबकि बेकाबू ट्रक डिवाइडर तोड़ते हुए क्षतिग्रस्त होकर सड़क के बीच जा पहुंचा. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे में पुलिस के चार जवानों सहित सात लोग घायल हो गये है। जिन्हे अस्पताल पहुंचाया गया। जिनका उपचार जारी है।

मोहब्बेवाला हाईवे पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसा आज सुबह हुआ। जानकारी के अनुसार, सीमेंट से लदा 12 टायरी ट्रक सहारनपुर की ओर से आ रहा था। आशारोड़ी चेक पोस्ट के पास ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और आगे चल रही आईआरबी की बस को पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद बस सड़क पर पलट गई। ट्रक की चपेट में एक मोटरसाइकिल भी आ गई। हादसे के समय आईआरबी फर्स्ट बटालियन की बस में जवानों समेत सात से आठ लोग





सवार थे। इनमें हेड कांस्टेबल ओमप्रकाश, चालक हेड कांस्टेबल हेमपाल सिंह, कांस्टेबल अदीप कुमार, कांस्टेबल प्रदीप राठौर और कांस्टेबल सुनील कुमार भी शामिल हैं। सभी जवान आईआरबी फर्स्ट बटालियन, बेलपड़ाव, रामनगर के बताए गए हैं। टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचा। घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार कराया जा रहा है। हादसे के कारण हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी में ट्रक के अनियंत्रित होने की बात सामने आई है। हादसे से जुड़े सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है, ताकि दुर्घटना की पूरी परिस्थितियां स्पष्ट हो सकें।

सवाल यह है कि जिस सड़क पर पुलिस की बस तक हादसे का शिकार हो रही है, वहां आम वाहन चालकों की सुरक्षा कितनी सुनिश्चित है?

दून वैली मेल

संपादकीय

निवेश की बड़ी छलांग

भारत और स्विट्जरलैंड के बीच 100 अरब डालर के निवेश और करीब 10 लाख रोजगार के अवसरों की दिशा में बढ़ती आर्थिक साझेदारी निश्चित रूप से उत्साहित करने वाली खबर है। यह समझौता ऐसे समय में सामने आ रहा है, जब भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है और वैश्विक कंपनियां चीन से आगे अपने निवेश विकल्पों को नए सिरे से तलाश रही हैं। भारत के लिए यह अवसर केवल विदेशी पूंजी आकर्षित करने का नहीं, बल्कि पूंजी के साथ तकनीक, कौशल, अनुसंधान, नवाचार और वैश्विक बाजार तक पहुंच मजबूत करने का भी है। स्विट्जरलैंड दुनिया की मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से लेकर फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा तकनीक, मशीनरी, घड़ी उद्योग, अनुसंधान और उच्च तकनीक वाले विनिर्माण तक उसकी विशेषज्ञता विश्वस्तरीय है। दूसरी ओर भारत के पास विशाल बाजार, बड़ी युवा आबादी, तेजी से बढ़ता डिजिटल ढांचा और कुशल मानव संसाधन की ताकत है। दोनों देशों की क्षमताओं का यह मेल आर्थिक सहयोग को नई दिशा दे सकता है। लेकिन किसी भी बड़े निवेश समझौते की असली सफलता उसकी घोषणा में नहीं, बल्कि उसके जमीन पर उतरने में होती है। 100 अरब डालर का आंकड़ा निश्चित रूप से बड़ा है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि यह पूंजी किन क्षेत्रों में आएगी, कितनी जल्दी आएगी और उससे कितने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के सामने आज सबसे बड़ी चुनौतियों में एक रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना है। भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है, लेकिन आर्थिक वृद्धि और रोजगार वृद्धि के बीच संतुलन बनाना अभी भी चुनौती है। आधुनिक तकनीक और स्वचालन के दौर में बड़ी पूंजी हमेशा बड़ी संख्या में रोजगार पैदा करे, यह जरूरी नहीं। इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्विट्जरलैंड से आने वाला निवेश केवल पूंजी-प्रधान क्षेत्रों तक सीमित न रहे। श्रम-प्रधान विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाओं, औषधि निर्माण, इलेक्ट्रानिक्स, इंजीनियरिंग, अनुसंधान और सेवा क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता मिले तो इसका रोजगार पर व्यापक असर हो सकता है। इस साझेदारी का एक महत्वपूर्ण पहलू तकनीक हस्तांतरण भी होना चाहिए। भारत विदेशी निवेश का ऐसा माडल विकसित करे, जिसमें विदेशी कंपनियां यहां केवल बाजार का लाभ उठाने के लिए न आएं, बल्कि स्थानीय स्तर पर उत्पादन करें, भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी करें और युवाओं को नई तकनीक का प्रशिक्षण दें। इससे विदेशी निवेश का लाभ कुछ बड़ी कंपनियों तक सीमित रहने के बजाय छोटे और मध्यम उद्यमों तक भी पहुंच सकेगा। भारत के राज्यों के लिए भी यह अवसर कम महत्वपूर्ण नहीं है। अब विदेशी निवेश की प्रतिस्पर्धा केवल केंद्र सरकार की नीतियों तक सीमित नहीं है। राज्यों को भी अपनी निवेश नीति, भूमि उपलब्धता, बिजली, परिवहन, कौशल विकास और प्रशासनिक मंजूरियों को निवेश-अनुकूल बनाना होगा। जो राज्य इस अवसर को समझेंगे, वह रोजगार और उद्योग दोनों में आगे निकल सकते हैं। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों के संदर्भ में भी इस साझेदारी से कई संभावनाएं निकल सकती हैं। पर्यटन, स्वास्थ्य, आयुष, जैविक कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा और पर्यावरण आधारित उद्योगों में निवेश आकर्षित किया जा सकता है। यदि विदेशी निवेश को स्थानीय संसाधनों और स्थानीय युवाओं की क्षमता से जोड़ा जाए तो इसका असर पलायन जैसी गंभीर समस्या पर भी पड़ सकता है। पहाड़ के युवाओं को रोजगार के लिए महानगरों की ओर जाने के बजाय अपने क्षेत्र में अवसर मिलें, तो निवेश का सामाजिक लाभ कहीं अधिक व्यापक होगा। हालांकि सरकार को इस पूरे प्रयास में सावधानी भी रखनी होगी। विदेशी निवेश का स्वागत होना चाहिए, लेकिन निवेश के नाम पर स्थानीय हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती। भूमि, पर्यावरण, जल संसाधन और स्थानीय रोजगार से जुड़े प्रश्नों को नीति निर्माण का हिस्सा बनाना होगा। हिमालयी राज्यों में तो यह और भी महत्वपूर्ण है, जहां विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन हमेशा चुनौती रहा है। इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि 100 अरब डालर की संभावित पूंजी में से कितना निवेश वास्तविक उत्पादन क्षमता बढ़ाने में जाता है और कितना वित्तीय या अन्य गतिविधियों में। भारत को केवल निवेश का आंकड़ा बढ़ाने की होड़ में नहीं पड़ना चाहिए। लक्ष्य ऐसा निवेश होना चाहिए, जो देश की उत्पादन क्षमता बढ़ाए, निर्यात को गति दे, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करे और भारतीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करे। 10 लाख रोजगार का लक्ष्य भी केवल सरकारी आंकड़ों की सफलता नहीं बनना चाहिए। रोजगार की गुणवत्ता, वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आज का युवा केवल नौकरी की संख्या नहीं, बल्कि सम्मानजनक आय और भविष्य की सुरक्षा चाहता है। इसलिए इस साझेदारी के तहत पैदा होने वाले रोजगार को कौशल, उत्पादकता और बेहतर जीवन स्तर से जोड़ना जरूरी होगा। भारत के लिए यह समय वैश्विक निवेश को आकर्षित करने का स्वर्णिम अवसर है। दुनिया की बड़ी कंपनियां आपूर्ति श्रृंखला में विविधता चाहती हैं। भारत के पास विशाल घरेलू बाजार, युवा कार्यबल और डिजिटल अर्थव्यवस्था की ताकत है। यदि इन ताकतों को बेहतर आधारभूत ढांचे और स्थिर नीतियों के साथ जोड़ा जाए तो भारत वैश्विक निवेश का बड़ा केंद्र बन सकता है। लेकिन इसके लिए लालफीताशाही से मुक्ति, समयबद्ध मंजूरियां, पारदर्शी नियम और नीतिगत निरंतरता अनिवार्य है। निवेशक को यह भरोसा चाहिए कि आज बनाई गई नीति कल अचानक नहीं बदलेगी। राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय भी जरूरी है। केवल शिखर बैठकों और बड़े समझौतों से निवेश नहीं आता। निवेशक को जमीन पर एक ऐसी व्यवस्था चाहिए, जिसमें कारोबार शुरू करने और चलाने में अनावश्यक अड़चनें न हों। भारत-स्विट्जरलैंड आर्थिक साझेदारी इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह देश के विकास की अगली कहानी में विदेशी पूंजी को एक नए अवसर के रूप में सामने रखती है। लेकिन अब सरकार और नीति-निर्माताओं की जिम्मेदारी बढ़ गई है। 100 अरब डालर का निवेश केवल सुर्खी न बने और 10 लाख नौकरियां केवल लक्ष्य बनकर न रह जाएं। इस समझौते की वास्तविक सफलता तब होगी, जब नए उद्योग खड़े हों, कारखानों में उत्पादन बढ़े, भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजार में उतरें, युवाओं को बेहतर कौशल मिले और रोजगार के नए दरवाजे खुलें। निवेश का अंतिम उद्देश्य आंकड़ों की चमक नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था की मजबूती और नागरिकों की समृद्धि होना चाहिए। भारत आज जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां पूंजी की जरूरत है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरत उत्पादक पूंजी की है। रोजगार की जरूरत है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरत सम्मानजनक रोजगार की है। स्विट्जरलैंड के साथ बढ़ती साझेदारी इस दिशा में बड़ा अवसर है। अब देखना यह है कि भारत इस अवसर को केवल समझौते की मेज पर रखता है या उसे कारखानों, प्रयोगशालाओं, कार्यालयों और युवाओं के रोजगार तक पहुंचाने में सफल होता है। 100 अरब डालर निवेश की बड़ी छलांग है, लेकिन 10 लाख नौकरियां उस छलांग की असली मंजिल।

चिट्ठी, यात्रा और बवाल

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ कांग्रेस की अंदरूनी सियासत एक बार फिर सार्वजनिक बहस के केंद्र में आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा को लेकर पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा की चिट्ठी और उसके बाद भी यात्रा जारी रहने से संगठन के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। एक अक्टूबर को सैलजा ने रावत को पत्र लिखकर यात्रा आगे न बढ़ाने का आग्रह किया था। उनका कहना था कि यात्रा को लेकर न तो प्रभारी के स्तर पर और न ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से चर्चा की गई।

मामला यहीं नहीं रुका। कांग्रेस नेतृत्व की आपत्ति के बावजूद रावत ने अपनी यात्रा जारी रखी। पांच अक्टूबर को जसपुर से हल्द्वानी की ओर यात्रा बढ़ी और रामनगर में समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। छह अक्टूबर को रामनगर में स्वागत के दौरान जेसीबी से पुष्पवर्षा किए जाने की खबर ने इस राजनीतिक घटनाक्रम को और चर्चा में ला दिया।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू यह है कि विवाद केवल एक यात्रा को लेकर नहीं है। इसके केंद्र में कांग्रेस में चुनावी अभियान का संचालन, संगठन की भूमिका और वरिष्ठ नेताओं की राजनीतिक सक्रियता का सवाल भी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि चुनावी दौर में पार्टी के कार्यक्रम संगठन के स्तर पर तय हों और व्यक्तिगत अभियानों से अलग सामूहिक गतिविधियों पर जोर दिया जाए। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से भी व्यक्तिगत अभियानों के बजाय पार्टी संगठन के तय कार्यक्रमों के अनुरूप गतिविधियां चलाने का संदेश दिया गया है।

रावत की ओर से यात्रा को जनसंवाद और जनता के प्रति आभार से जोड़ा जा रहा है। दूसरी ओर, पार्टी नेतृत्व की आपत्ति का आधार संगठनात्मक समन्वय बताया गया है। यही अंतर अब राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है। एक पक्ष इसे जनता के बीच जाने की राजनीतिक कवायद मान रहा है तो दूसरा इसे संगठन की अनुमति और सामूहिक रणनीति के दायरे में देखने पर जोर दे रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के लिए इस घटनाक्रम का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं है। ऐसे समय में पार्टी के भीतर होने वाली हर राजनीतिक गतिविधि का संदेश कार्यकर्ताओं और जनता तक जाता है। एक तरफ कांग्रेस भाजपा के खिलाफ सरकार, रोजगार, महंगाई, विकास और अन्य मुद्दों को लेकर अपना अभियान तेज करना चाहती है, वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ नेताओं के अलग-अलग कार्यक्रम संगठनात्मक एकजुटता के सवाल खड़े कर रहे हैं।

◆कांग्रेस के भीतर टकराव, प्रभारी कुमारी सैलजा की आपत्ति के बावजूद रावत आगे बढ़े
◆चुनावी तैयारी के बीच संगठन और व्यक्तिगत राजनीतिक अभियान के बीच खिंची लकीर
◆उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ कांग्रेस की अंदरूनी सियासत हुई तेज

कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि वह वरिष्ठ नेताओं की व्यक्तिगत राजनीतिक सक्रियता और पार्टी की सामूहिक चुनावी रणनीति के बीच संतुलन कैसे बनाती है। रावत लंबे समय से उत्तराखंड की राजनीति का प्रमुख चेहरा रहे हैं। ऐसे में उनकी राजनीतिक सक्रियता का असर केवल उनके व्यक्तिगत कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहता। उनके कार्यक्रमों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भागीदारी स्वाभाविक रूप से संगठन के भीतर संदेश पैदा करती है। दूसरी तरफ प्रदेश प्रभारी का तर्क भी स्पष्ट है कि चुनावी वर्ष में समानांतर कार्यक्रम पार्टी की सामूहिक रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं। कांग्रेस नेतृत्व ने इसी कारण व्यक्तिगत अभियानों के बजाय सामूहिक कार्यक्रमों पर जोर दिया है।

विवाद बढ़ने के बाद रावत को कांग्रेस नेतृत्व ने दिल्ली बुलाया है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार पार्टी नेतृत्व उनसे इस पूरे घटनाक्रम पर बातचीत करेगा और उनका पक्ष सुनने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। सात या आठ अक्टूबर को बातचीत की संभावना बताई गई है। इससे साफ है कि उत्तराखंड की यह चिट्ठी अब देहरादून तक सीमित नहीं रही। मामला दिल्ली तक पहुंच चुका है। कांग्रेस हाईकमान के

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

कांग्रेस के 'आंतरिक लोकतंत्र' पर सवाल

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। कांग्रेस की ओर से लोकतंत्र और मतदाता अधिकारों को लेकर चलाए जा रहे अभियान के बीच उत्तराखंड में पार्टी की अंदरूनी खींचतान भाजपा के निशाने पर आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा की आपत्ति और पार्टी नेतृत्व के स्तर से व्यक्तिगत अभियान के बजाय सामूहिक कार्यक्रमों पर जोर दिए जाने के बाद भाजपा ने कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जो पार्टी देश में लोकतंत्र बचाने का अभियान चला रही है, उसी के भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने हरीश रावत की यात्रा को लेकर कांग्रेस नेतृत्व के रुख पर निशाना साधते हुए कहा कि जब पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता को अपनी यात्रा निकालने की स्वतंत्रता नहीं है तो सामान्य कार्यकर्ता की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।

भट्ट का यह हमला ऐसे समय में आया है, जब हरीश रावत की यात्रा को लेकर कांग्रेस में मतभेद सार्वजनिक हो चुके हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने एक अक्टूबर को रावत को पत्र लिखकर यात्रा आगे नहीं बढ़ाने का आग्रह किया था। पत्र में कहा गया था कि यात्रा के संबंध में प्रदेश प्रभारी अथवा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से चर्चा नहीं हुई और चुनावी समय में समानांतर कार्यक्रम पार्टी के हित में नहीं होंगे। इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी स्पष्ट किया कि आगामी चुनाव के लिए अभियान सभी नेताओं को साथ लेकर पार्टी के बैनर तले चलाया जाएगा और व्यक्तिगत अभियानों को पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। रावत को इस मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए दिल्ली बुलाया गया है।

भाजपा अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अभियान को उत्तराखंड के घटनाक्रम से जोड़कर राजनीतिक हमला कर रही है। कांग्रेस देशभर में चुनावी प्रक्रिया और मतदाता अधिकारों को लेकर वोट बचाओ, लोकतंत्र बचाओ अभियान चला रही है। इसी दौरान उत्तराखंड में पार्टी के एक वरिष्ठ नेता की यात्रा को लेकर प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के बीच मतभेद सामने आने से भाजपा को कांग्रेस पर पलटवार का अवसर मिला है।

◆महेंद्र भट्ट का तंज शीर्ष नेता की यात्रा की आजादी नहीं तो सामान्य कार्यकर्ता का क्या हाल
◆हरीश रावत को राजनीति से संन्यास की सलाह, कांग्रेस ने कहा- यात्रा जनसंवाद का कार्यक्रम
◆प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के बीच मतभेद पर भाजपा को कांग्रेस पर पलटवार का मिला अवसर

भाजपा का तर्क है कि कांग्रेस को पहले अपने संगठन के भीतर संवाद और निर्णय की व्यवस्था को लेकर स्पष्टता दिखानी चाहिए। पार्टी का हमला इसी राजनीतिक विरोधाभास को रेखांकित करने पर केंद्रित है। एक ओर कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा का सवाल उठा रही है, दूसरी ओर उसके ही वरिष्ठ नेता के कार्यक्रम को लेकर संगठनात्मक असहमति सामने आ रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से रावत की यात्रा को जनसंवाद कार्यक्रम बताया गया है। रावत ने भी हल्द्वानी में कहा कि उनकी यात्रा का कोई राजनीतिक मकसद नहीं है।

महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत को राजनीति से संन्यास लेने की सलाह देकर इस विवाद को और राजनीतिक रंग दे दिया। भाजपा अध्यक्ष का तर्क है कि जब कांग्रेस में ही रावत का सम्मान नहीं बचा है तो उन्हें अपनी राजनीतिक भूमिका पर विचार करना चाहिए। भाजपा की यह टिप्पणी हालांकि केवल संगठनात्मक विवाद तक सीमित नहीं है। हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे प्रमुख और लंबे समय से सक्रिय नेताओं में हैं। ऐसे में उनकी यात्रा पर पार्टी नेतृत्व की आपत्ति और उसके बाद भाजपा का हमला चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को लेकर नए सवाल खड़े कर रहा है। दिलचस्प यह भी है कि रावत ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा था कि वह पार्टी और उत्तराखंड के लिए सिपाही की तरह काम करेंगे तथा कांग्रेस और गांधी-नेहरू परिवार को छोड़ने का सवाल नहीं है। ऐसे में भाजपा की संन्यास की सलाह का राजनीतिक जवाब भी कांग्रेस खेमे से आना तय माना जा रहा है।

हरीश रावत की यात्रा को लेकर कांग्रेस के भीतर भले ही संगठनात्मक सवाल उठे हों, लेकिन यात्रा में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की भागीदारी भी सामने आई

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

यातायात नियम तोड़ने वालों पर 174 वाहन चालकों के चालान

अल्मोड़ा(आरएनएस)। पर्यटन सीजन के मद्देनजर यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के लिए अल्मोड़ा पुलिस ने जिलेभर में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 174 वाहन चालकों के खिलाफ एमवी एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोडके ने पर्यटन सीजन को देखते हुए सभी थाना-चौकी प्रभारियों और यातायात पुलिस को व्यापक वाहन चेकिंग अभियान चलाने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। निर्देशों के क्रम में जिले के सभी थाना प्रभारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस की ओर से जिले के प्रवेश मार्गों पर वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही नगर क्षेत्रों, प्रमुख बाजारों, चौराहों और पर्यटन स्थलों के आसपास भी लगातार निगरानी एवं चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बढ़ते पर्यटन के बीच सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए शराब पीकर वाहन चलाने, रैश ड्राइविंग तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। अल्मोड़ा पुलिस ने आमजन और पर्यटकों से यातायात नियमों का पालन करने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने और नशे की हालत में वाहन न चलाने की अपील की है। पुलिस ने स्वयं और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की भी अपील की है।

राज्य आंदोलनकारी घोषित न किए जाने पर जताई नाराजगी

पिथौरागढ़(आरएनएस)। वंचित राज्य आंदोलनकारियों ने चिह्नितकरण न होने पर नाराजगी जाहिर की है। वंचित राज्य आंदोलनकारियों ने डीएम के माध्यम से सीएम को पत्र भेजने का निर्णय लिया है। नगर के स्वरांजलि नृत्य वाटिका में वंचित राज्य आंदोलनकारियों की बैठक हुई। बैठक में राज्य आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के बावजूद अभी तक आंदोलनकारी घोषित नहीं किए जाने पर गहरी चिंता और नाराजगी व्यक्त की गई। उमा पाण्डेय ने कहा कि राज्य निर्माण के संघर्ष में अपना योगदान देने वाले कई लोग आज भी अपने अधिकार से वंचित हैं। लंबे समय से वंचित आंदोलनकारियों को आंदोलनकारी का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई जा रही है, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है।6 अक्तूबर को जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। उसके बाद आगे बैठक कर रणनीति तैयार की जाएगी। इस दौरान पार्वती भट्ट, मीनू पुनेडा, राजेंद्र पांडे, गोविंद बोहरा, राम सिंह बिष्ट, सुरेश जोशी, जीवन फुलेरा, रघुवीर सिंह, बलवंत सिंह, पूरन सिंह कन्याल, प्रमोद पंत, भास्कर दत्त भट्ट, त्रिभुवन जोशी, दिनेश जोशी एवं माधव सिंह पंगरिया मौजूद रहे।

जिला अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ ने किया कार्यभार ग्रहण

उत्तरकाशी(आरएनएस)। सीमांत जनपद के मरीजों के लिए राहत की खबर है। जिला अस्पताल उत्तरकाशी में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को और मजबूती मिली है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अंजली सिसोदिया ने जिला चिकित्सालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसके साथ ही सोमवार से एक सर्जन और एक बाल रोग विशेषज्ञ रोस्टरवार अस्पताल में सेवाएं देंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. श्याम विजय ने बताया कि जनपद में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए महानिदेशालय स्तर पर लगातार पत्राचार और समन्वय किया जा रहा था। इन्हीं प्रयासों के परिणामस्वरूप रोस्टरवार विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं जिला अस्पताल को उपलब्ध कराई गई हैं। डॉ. विजय ने कहा कि बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती से बच्चों को जिला स्तर पर ही विशेषज्ञ परामर्श और उपचार मिल सकेगा। वहीं सर्जन की सेवाएं उपलब्ध होने से मरीजों को आवश्यक सर्जिकल परामर्श के लिए बाहर जाने की आवश्यकता कम होगी।

शीतकालीन यात्रा को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने की मांग

उत्तरकाशी(आरएनएस)। शीतकालीन चारधाम यात्रा को केवल धार्मिक गतिविधि तक सीमित रखने के बजाय इसे गांवों की अर्थव्यवस्था और रोजगार को जोड़ने की मांग उठी है। चारधाम होटल एसोसिएशन ने गढ़वाल आयुक्त को आठ सूत्री ज्ञापन सौंपकर शीतकालीन गद्दीस्थलों को ग्रामीण तीर्थाटन केंद्र के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया है।यमुनोत्री क्षेत्र में विकासनगर के कट्टापत्थर स्थित आरटीओ चेकपोस्ट व्यवस्था समाप्त करने व जानकीचट्टी-यमुनोत्री पैदल मार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए वैकल्पिक मार्ग विकसित करने की मांग की गई। खरसाली में स्वास्थ्य, शौचालय, विद्युत और पेयजल सुविधाओं को मजबूत करने के साथ मुखबा-जंगला मोटर मार्ग का निर्माण जल्द पूरा करने और मुखबा में हेलिपैड बनाने की मांग रखी गई। पांडुकेश्वर के योगध्यान मंदिर की क्षतिग्रस्त एप्रोच रोड के सुदृढ़ीकरण का मुद्दा भी उठाया गया।

वोटर लिस्ट के 'शुद्धीकरण' पर सियासत

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी होने के साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज हो गया है। मतदाता सूची में बड़े बदलाव को लेकर कांग्रेस जहां चुनावी प्रक्रिया और नाम हटाए जाने पर सवाल उठा रही है, वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए इसे मतदाता सूची के शुद्धीकरण की प्रक्रिया बताया है। दोनों दलों के बीच अब बहस इस बात पर केंद्रित हो गई है कि सूची से घटे नामों का वास्तविक स्वरूप क्या है और इसका राजनीतिक असर किस रूप में देखा जाए।

भाजपा ने कांग्रेस के उन आरोपों को खारिज किया है, जिनमें वर्ग विशेष के मतदाताओं के नाम निशाने पर होने की बात कही जा रही है। भाजपा का तर्क है कि यदि किसी खास वर्ग को निशाना बनाकर नाम हटाए गए होते तो नामों में कमी का भौगोलिक और सामाजिक पैटर्न अलग दिखाई देता। पार्टी नेताओं ने कहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में नाम घटे हैं, जबकि वहां उस वर्ग की आबादी अपेक्षाकृत कम है। भाजपा इसे कांग्रेस के आरोपों पर सवाल उठाने वाला तथ्य बता रही है।

दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि एसआईआर के बाद बड़ी संख्या में मतदाता सूची से बाहर हुए हैं और चुनाव आयोग को विधानसभा-वार पूरा विवरण सार्वजनिक करना चाहिए। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने दावा किया है कि प्री-एसआईआर और एसआईआर के दौरान 13 लाख से अधिक नाम हटाए गए और इनके बारे में विस्तृत जानकारी सामने आनी चाहिए।

एसआईआर के बाद उत्तराखंड की अंतिम मतदाता सूची में 71,58,949 मतदाता दर्ज हैं। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार पिछली सूची की तुलना में मतदाताओं की संख्या में करीब आठ लाख से अधिक की कमी आई है। हालांकि, यह कमी अपने आप में यह साबित नहीं करती कि किसी खास राजनीतिक या सामाजिक वर्ग के मतदाताओं को जानबूझकर हटाया गया। चुनाव आयोग ने नामों की जांच, दावे-आपत्तियां और पात्र लोगों को दोबारा नाम जुड़वाने की प्रक्रिया का प्रावधान रखा है। आयोग ने अंतिम सूची के बाद भी ऐसे मतदाताओं की पहचान और पुन: पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

यही वह बिंदु है जहां राजनीतिक आरोप

◆वर्ग विशेष को निशाना बनाने के आरोपों को भाजपा ने किया खारिज, पर्वतीय क्षेत्रों के आंकड़े दे पेश की सफाई

◆सूची में नामों की कटौती पर कांग्रेस हमलावर, भाजपा ने बताया चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता

◆नाम घटने को लेकर दावों और प्रतिदावों से गरमाई उत्तराखंड राज्य में चुनावी राजनीति

और प्रशासनिक प्रक्रिया अलग-अलग दिखाई देती हैं। कांग्रेस सूची में कमी को लेकर सवाल उठा रही है, जबकि भाजपा इसे मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत कर रही है। भाजपा ने कांग्रेस के वर्ग विशेष के वोट काटे जाने के आरोप पर पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के आंकड़ों को राजनीतिक बहस का आधार बनाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार एसआईआर के बाद मैदानी क्षेत्रों की 36 विधानसभा सीटों में पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में लगभग दोगुने मतदाता घटे हैं।

भाजपा इसी तथ्य को कांग्रेस के आरोपों के जवाब के रूप में इस्तेमाल कर रही है। पार्टी का तर्क है कि यदि किसी खास समुदाय को निशाना बनाकर नाम हटाए गए होते तो केवल भौगोलिक आधार पर ऐसी तस्वीर सामने नहीं आती। लेकिन यहां भी अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले विधानसभा-वार, बूथ-वार और कारण-वार आंकड़ों का विश्लेषण जरूरी है। केवल कुल संख्या के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि नाम किन कारणों से हटे। मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, दोहराए गए या सत्यापन में संपर्क न हो पाने वाले मतदाताओं की अलग-अलग श्रेणियां हैं।

एसआईआर का विवाद ऐसे समय सामने आया है जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो रही हैं। इसलिए मतदाता सूची में हुआ बदलाव स्वाभाविक रूप से राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। भाजपा इसे साफ-सुथरी मतदाता सूची की दिशा में कदम बता रही है, जबकि कांग्रेस पारदर्शिता और नामों के विलोपन की प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है।

भाजपा नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस मतदाता सूची को लेकर भ्रम पैदा कर रही है और लोकतंत्र बचाने के नाम पर राजनीतिक मुद्दा खड़ा कर रही है। इसके जवाब में कांग्रेस का कहना है कि मतदाता सूची से पात्र लोगों का नाम छूटना लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ा गंभीर विषय है। इस टकराव में सबसे महत्वपूर्ण सवाल राजनीतिक बयान नहीं, आंकड़ों की पारदर्शिता है। यदि चुनाव आयोग विधानसभा-वार और कारण-वार विवरण सार्वजनिक करता है तो विवाद के कई सवालों का तथ्यात्मक जवाब मिल सकता है। इससे न केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की गुंजाइश घटेगी, बल्कि पात्र मतदाताओं के नाम वापस जोड़ने की प्रक्रिया भी अधिक भरोसेमंद होगी।

उत्तराखंड की राजनीति में एसआईआर अब महज प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गई है। भाजपा इसे मतदाता सूची के शुद्धीकरण और कांग्रेस के आरोपों के जवाब के रूप में देख रही है, जबकि कांग्रेस इसे मताधिकार और चुनावी पारदर्शिता से जोड़ रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों दलों की राजनीतिक रणनीति में मतदाता सूची महत्वपूर्ण मुद्दा बनी रह सकती है। लेकिन अंतिम तस्वीर राजनीतिक दावों से नहीं, बूथ स्तर के आंकड़ों और पात्र मतदाताओं के नामों की स्थिति से स्पष्ट होगी। 2027 के चुनाव से पहले उत्तराखंड में अब लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं, वोटर लिस्ट के नैरेटिव की भी है कि भाजपा इसे शुद्धीकरण बता रही है, कांग्रेस इसे सवालों के घेरे में रख रही है। फैसला आरोपों से नहीं, सार्वजनिक आंकड़ों से होगा।

स्कूली बच्चों के समय के अनुसार एलआर साह रोड की यातायात व्यवस्था में बदलाव

अल्मोड़ा(आरएनएस)। स्कूली बच्चों के विद्यालय समय में हुए बदलाव को देखते हुए अल्मोड़ा पुलिस ने एलआर साह रोड पर यातायात व्यवस्था में आंशिक संशोधन किया है। संशोधित व्यवस्था के तहत निर्धारित समय में फायर स्टेशन अल्मोड़ा से शिखर तिराहे की ओर आने वाले सभी चार पहिया वाहनों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस के अनुसार प्रात: 8:30 बजे से 9:45 बजे तक तथा सायं 2:30 बजे से 4:30 बजे तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यकतानुसार यातायात को वैकल्पिक मार्गों से संचालित किया जाएगा। निर्धारित समयावधि के अतिरिक्त एलआर साह रोड पर यातायात व्यवस्था पूर्व की भांति संचालित रहेगी। अल्मोड़ा पुलिस ने वाहन चालकों से संशोधित यातायात व्यवस्था का पालन करने, पुलिस को सहयोग देने और निर्धारित समय में वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की अपील की है।

पुरानी पेंशन बहाली और टीईटी की अनिवार्यता के विरोध पर शिक्षकों का मंथन

विकासनगर(आरएनएस)। पुरानी पेंशन योजना की बहाली और शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (एबीआरएसएम) ने आंदोलन की रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। हुई संगठन की बैठक में शिक्षक हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। पदाधिकारियों ने कहा कि पुरानी पेंशन शिक्षकों के भविष्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जबकि टीईटी की अनिवार्यता को लेकर भी शिक्षकों की चिंताओं को सरकार और संबंधित मंचों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाएगा। गढ़वाल मंडल अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने कहा कि शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान के लिए संगठन को एकजुट होकर प्रभावी पहल करनी होगी। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को प्रमुखता से उठाने पर जोर दिया। साथ ही शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता के संबंध में संगठन का पक्ष मजबूती से रखने और आवश्यक स्तर पर संवाद करने की बात कही। बैठक में शिक्षकों की सेवा-शर्तों, अन्य लंबित समस्याओं और शिक्षक हितों से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। पदाधिकारियों ने कहा कि इन मुद्दों को उचित मंच पर उठाने के साथ ही संगठन की आगामी गतिविधियों और रणनीति को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और अधिक से अधिक शिक्षकों को गतिविधियों से जोड़ने पर भी जोर दिया गया। मुख्य अतिथि श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज सहसपुर के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य एवं राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त डॉ. रविन्द्र कुमार सैनी ने शिक्षक हितों से जुड़े विषयों को संगठित तरीके से उठाने को जरूरी बताया। जिलाध्यक्ष डॉ. नीरज कुमार सैनी, मंत्री तजेंद्र धीमान, मीडिया प्रभारी एसके सैनी, चतर सिंह नेगी, पीयूष पांडेय, धर्मेंद्र कुमार, रमन समेत संगठन के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।

क्या है डांस मेडिटेशन? इसे दिनचर्या का हिस्सा बनाने से मिलते हैं कई लाभ

डांस मेडिटेशन एक अनोखी विधि है, जिसमें नाचते हुए ध्यान लगाया जाता है। यह एक प्रकार का ध्यान है, जिसमें आप अपने शरीर को स्वतंत्र रूप से हिलाते-डुलाते हैं और अपने मन को शांत करते हैं। इस विधि का उद्देश्य मानसिक तनाव को कम करना और आत्मविश्वास बढ़ाना है। डांस मेडिटेशन से आप न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी संतुलित रहते हैं। आइए इसके फायदे और तकनीक के बारे में जानें।

डांस मेडिटेशन के फायदे : डांस मेडिटेशन कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। यह तनाव को कम करने में मदद करता है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। इसके अलावा यह आत्मविश्वास बढ़ाने और आत्म-अनुशासन सिखाता है। डांस मेडिटेशन से आप अपने शरीर को सक्रिय रखते हुए फिट और स्वस्थ रह सकते हैं। यह विधि न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक रूप से भी आपको मजबूत बना सकती है और जीवन में सकारात्मकता लाती है।

ऐसे करें डांस मेडिटेशन : डांस मेडिटेशन करने के लिए सबसे पहले एक शांत जगह चुनें, जहां आप बिना किसी रुकावट के नाच सकें। हल्का संगीत लगाएं और अपनी पसंदीदा धुन पर नाचें। ध्यान रखें कि यहां कोई सही या गलत तरीका नहीं होता, बस अपने मन की सुने और खुलकर नाचें। शुरूआत में कुछ सरल मूव्स आजमाएं, फिर धीरे-धीरे अपने स्टाइल में बदलाव करें। इस दौरान गहरी सांस लें और अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें।

संगीत का चयन कैसे करें? : संगीत का चयन डांस मेडिटेशन का अहम हिस्सा है। ऐसा संगीत चुनें, जो आपको खुशी दे और आपकी ऊर्जा बढ़ाए। तेज धुन या धीमी धुन, जो भी आपको पसंद हो, उसे सुनें और उसी पर नाचें। अगर आप शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो वह भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा लोक संगीत या कोई भी ऐसा गाना, जो आपके मन को प्रसन्न करे, उसे सुनें और नाचें। इससे आपका मन खुश रहेगा और आप बेहतर महसूस करेंगे।

ध्यान केंद्रित करने के तरीके : डांस करते समय ध्यान केंद्रित करना जरूरी है, ताकि आपका मन शांत रहे। इसके लिए आप गहरी सांस लें और अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। सोचने के बजाय बस महसूस करें कि आपका शरीर कैसे हिल रहा है, इससे आपका मन शांत रहेगा और आप पूरी तरह से डांस में डूब जाएंगे। इसके अलावा आप अपने शरीर की हर हरकत को महसूस करें और उसे पूरी तरह से जीएं।

स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है कोई धुन गुनगुनाना, जानिए इससे मिलने वाले लाभ

कोई धुन गुनगुनाना एक सरल और आरामदायक गतिविधि है, जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर अच्छा असर डाल सकती है। यह न केवल तनाव को कम करता है, बल्कि हमारे मूड को भी बेहतर बनाता है। गुनगुनाने से शरीर में खुश करने वाले हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जो हमें खुश और संतुलित महसूस कराता है। इसके अलावा यह हमारी सांसों को भी नियंत्रित करता है। आइए जानते हैं कि कैसे गुनगुनाने से कई फायदे मिल सकते हैं।

तनाव को कम करने में मददगार : गुनगुनाना एक बहुत अच्छा तरीका है, जिससे हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। जब हम गुनगुनाते हैं तो हमारे दिमाग में खुशी देने वाले हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जो हमें खुश और संतुलित महसूस कराता है। इस प्रक्रिया में हमारी सांसें भी नियंत्रित होती हैं, जिससे हमें शांति मिलती है। गुनगुनाने से न केवल हमारा मूड बेहतर होता है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है और हमें ताजगी का अनुभव कराता है।

मनोदशा को बनाता है बेहतर : गुनगुनाने से हमारी मनोदशा भी बेहतर होती है। जब हम गुनगुनाते हैं तो हमारे दिमाग में खुशियों का एहसास होता है, जिससे हमारी ऊर्जा सकारात्मक रहती है। यह आदत हमें नकारात्मक विचारों से दूर रखती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है। इसके अलावा गुनगुनाना एक सरल और आरामदायक गतिविधि है, जिसे हम कहीं भी कर सकते हैं। इससे हमारा मूड और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और हम अधिक खुश और संतुलित महसूस करते हैं।

सांसों को करता है नियंत्रित : गुनगुनाना हमारी सांसों को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। जब हम गुनगुनाते हैं तो हमारी सांसें गहरी और स्थिर होती हैं, जिससे फेफड़ों को अधिक ऑक्सीजन मिलता है। यह प्रक्रिया हमारे शरीर को ऊर्जा देती है और ताजगी का अनुभव कराती है। इसके अलावा गुनगुनाने से तनाव कम होता है और मन शांत होता है। इस तरह गुनगुनाना एक सरल और प्रभावी तरीका है, जिससे हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं।

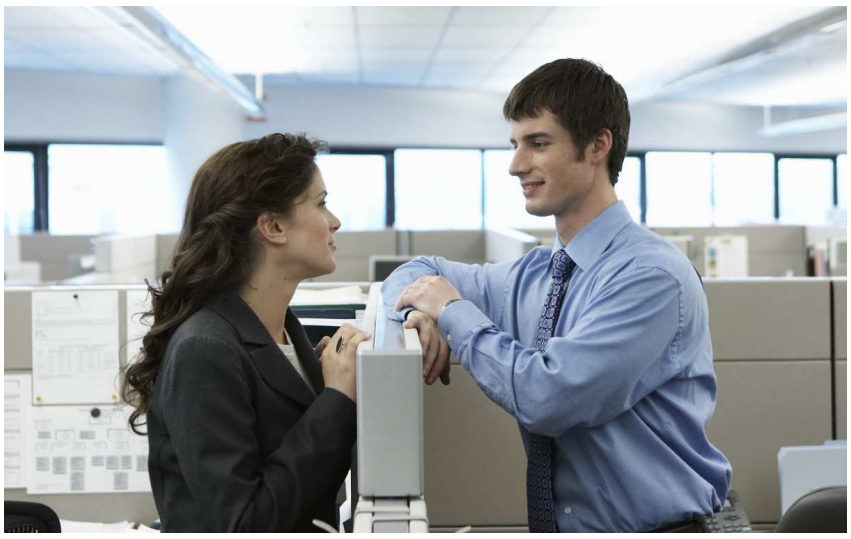
नींद में लाता है सुधार : गुनगुनाना नींद में सुधार लाने में भी सहायक है। सोने से पहले कुछ मिनट गुनगुनाने से हमारा मन शांत होता है और नींद जल्दी आती है। यह आदत हमें अच्छी नींद दिलाती है।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *सांध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

–प्रबंधक विज्ञापन

ऑफिस में किसी से शेयर न करें ये बातें



एक आम इंसान अपनी जिंदगी का करीब एक-तिहाई हिस्सा दफ्तर में बिताता है। जाहिर है ऐसे में ऑफिस में साथ काम करने वालों से एक रिश्ता बन ही जाता है। कुछ ऑफिस के साथी अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो कुछ से प्रतिस्पर्धा भी होती है। ऑफिस के साथी अक्सर सुख-दुख में काम भी आते हैं। हम दफ्तर के साथियों के साथ कई बातें शेयर भी करते हैं। हालांकि दफ्तर में साथियों से अच्छा रिश्ता बनाए रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। बेमतलब की बहस, अपनी अच्छी छवि बनाने और प्रोफेशनल रिश्ता कायम रखने के लिए यह जानना जरूरी है कि अपने साथियों के साथ कैसे और कौन सी बात की जाए। आइए आपको बताते हैं कि कुछ ऐसी बातें जो ऑफिस के साथियों के साथ शेयर न करना ही बेहतर है।

आपकी पर्सनल बातें

ऑफिस में लोग काम करने आते हैं और उन्हें आपकी निजी बातों से लेना-देना नहीं होता। बेहतर है कि अपने परिवार या रिश्तों से जुड़ी जानकारी आप खुद तक ही रखें। जाहिर है ऑफिस के साथी आपकी घरेलू जिंदगी के बारे में थोड़ा-बहुत तो जानते ही हैं लेकिन अपनी अंतरंग बातें जैसे पारिवारिक या रिलेशनशिप के झगड़े, पैसे की परेशानी या काम के बाहर के दोस्तों से जुड़ी बातों को ऑफिस में शेयर करना सही नहीं है। याद रखिए जो बात आपके जीवन के लिए कोई बेहद मायने रखती है, वह दूसरों के लिए सिर्फ गॉसिप का विषय हो सकती है।

काम या कंपनी को लेकर शिकायत

हर कर्मचारी को कंपनी या काम से कुछ न कुछ शिकायत होती है और छोटी-मोटी बातें साथियों के साथ बात करके ठीक भी की जा सकती हैं। हालांकि अगर आप कंपनी या काम से बहुत असंतुष्ट हैं तो साथियों से इस बारे में बात करने के बजाय अपनी बात सही तरीके से उचित अधिकारियों तक पहुंचाना बेहतर विकल्प है। बार-बार शिकायत करना आपके साथियों के मन में आपके प्रति सवाल पैदा करता है और एक और कर्मचारी के तौर पर आपकी इमेज खराब होती है।

दूसरे साथियों के बारे में आपकी राय

अक्सर ऑफिस में दो लोगों के बीच बातचीत का सबसे पसंदीदा विषय कोई तीसरा साथी होता है। याद रखिए अगर कोई सहकर्मी आपसे किसी और के बारे में बात कर रहा है या शिकायत कर रहा है तो संभव है कि वह आपके बारे में भी ऐसा करता होगा। किसी के भी सामने अपने सहकर्मी के बारे में कोई नेगेटिव राय जताने से बचें क्योंकि यह बाद में आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। अगर ऑफिस में किसी के काम या व्यवहार से आपको समस्या है तो इस बात को किसी अन्य साथी के बजाय बॉस के सामने रखना बेहतर होगा।

अपनी सोशल नेटवर्किंग लाइफ

आजकल जमाना सोशल नेटवर्किंग का है और आपकी ऑनलाइन गतिविधियां ऑफिस में चर्चा का विषय बन सकती हैं। अपनी सोशल नेटवर्किंग लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ से अलग रखें। आपके स्टेटस या ब्लॉग पर आपके विचार से लोग ऑफिस में आपके बारे में धारणा बना सकते हैं। ऑफिस या काम से जुड़ी बात तो सोशल नेटवर्क पर बिल्कुल शेयर न करें और संभव हो सके तो ऑफिस के दोस्तों को सोशल नेटवर्क पर दोस्त बनाने से बचें।

आपकी कमाई और खर्च

भले ही हर कंपनी अपने कर्मचारियों को एक-दूसरे को सैलरी बताने से मना करती है लेकिन अक्सर लोगों को यह बात पता चल ही जाती है। फिर भी खुलकर अपनी सैलरी या कमाई पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। साथ ही अपने इस हफ्ते कितनी शॉपिंग की या छुट्टियां कितने महंगे होटल में बिताई जैसी डीटेल्स ऑफिस में बताने की जरूरत नहीं है।

वीकेंड की मस्ती

कल तो मैंने इतनी पी ली थी- अक्सर लोग दफ्तर में ऐसी कहानियां सुनाते मिल जाते हैं। लोग भले ही आपकी पिछली रात या वीकेंड की मस्ती और आज के हैंगओवर की कहानी सुनकर मजे लेते हों लेकिन इससे आपकी छवि बिगड़ती ही है। इससे आपके साथियों के बीच आप पर भरोसा कम होता है और आपकी प्रोफेशनल छवि कमजोर होती है।

शब्द सामर्थ्य - 64

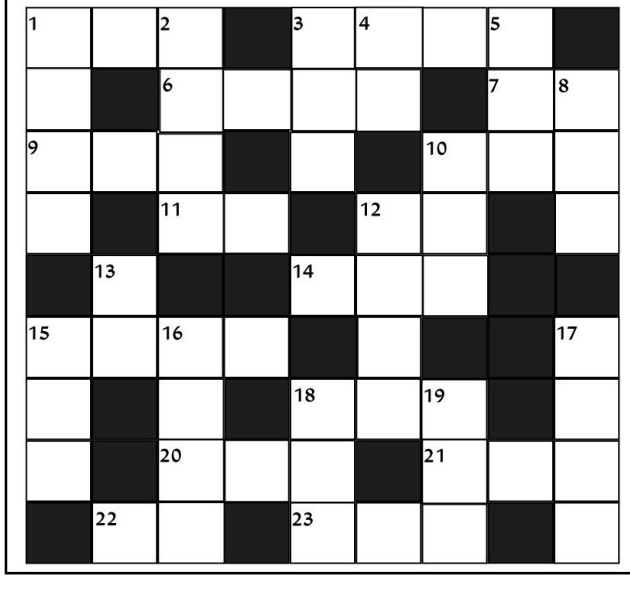
(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. रूचिकर लगने वाली, रूचि के अनुकुल, चुनी हुई 3. राजाओं के बैठने का आसन 6. श्रमिक 7. कार्य, काज 9. वाद्ययंत्र आदि बजाने वाला 10. सहारा, सहायक वस्तु 11. शर्म, लाज, हया 12. मक्खन, माखन 14. श्रीमती राबड़ी देवी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं 15. चंद्रमा, रजनीश, चांद 18. पुस्तक 20. अवधि, समय 21. तर्क वितर्क और कहा-सुनी, जबानी झगड़ा 22. सूरत, आकार 23. झुका हुआ, नत।

ऊपर से नीचे

1. पंद्रह दिन का समय, शुक्ल या कृष्ण पक्ष 2. आग बुझाने की मशीन 3. हिंदु विवाहित स्त्री के मांग में भरने का लाल चूर्ण 4. पराजय, माला 5. मुंह ढकने का कपड़ा, घुंघट 8. चंदन, दक्षिण का एक पर्वत 10. व्यवस्थित करना, सजाना, स्वभाव आदि का परिष्कार, शुद्ध संबंधी कृत्य 12. विशालता, बड़प्पन, महान होने का भाव 13. अड़चन, रुकावट 15. जमीन के अंदर गहरा और लंबा रास्ता, अच्छे रंग का 16. बेवकूफ, मूर्ख, अहमक 17. औसत के हिसाब से 18. कृषक 19. अधिक, ज्यादा।



शब्द सामर्थ्य क्रमांक 63 का हल

ज	ल		आ	वा	जा	ही		
मा		खू	ब		दू	र	स्थ	
ना	दा	न		सा	ग		ल	क्ष्य
	न	ख		त	र	ल		
	वी	रा	न			च	ट	क
	र	ब		आ	ज	क	ल	
			आ	ग		दा	ना	
	अ	ग	र	म	ग	र		क्रो
भा	भी		ती	न			व	ध



किसान मजदूर महासंग्राम संगठन ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन

संवाददाता

देहरादून। किसान मजदूर महासंग्राम संगठन ने एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। आज यहां किसान मजदूर महासंग्राम संगठन के कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष मोबीन अहमद के नेतृत्व में एसएसपी कार्यालय पहुंचे जहां पर उन्होंने प्रदर्शन कर एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि संगठन के राष्ट्रीय मुख्यालय में पीडित परिवार अपनी शिकायतें लेकर आ रहे हैं। जैसे कि एक मामला देहरादून में नाबालिग की करंट लगने से हुई मृत्यु का है। उसकी मां उनके पास यह मामला लेकर पहुंची। ऐसे कई मामले उनके पास आए है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। पीडित परिवार अपनी शिकायत लेकर जनपद के विभिन्न चौकी व थानों के चक्कर लगाने को मजबूर है। कई मामलों में पीडितों द्वारा बार-बार शिकायत प्रार्थना पत्र देने के बावजूद उन्होंने कई सप्ताह, कई महीने तक कार्रवाही की प्रतीक्षा करनी पडती है। पीडित परिवार न्याय एवं सुरक्षा की उम्मीद लेकर पुलिस प्रशासन के पास पहुंचते है। ऐसे में यदि उनकी शिकायतों पर समय से कार्रवाही नहीं होती है जो उन्हें मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पडता है। उन्होंने मांग की है कि जनपद में लम्बित शिकायतों एवं पीडित परिवारो की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जायें। एसएसपी ने उनको कार्रवाही का आश्वासन दिया।

शराब के साथ दो गिरफ्तार

संवाददाता

देहरादून। पुलिस ने शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रायवाला थाना पुलिस ने सौंग नदी के पास एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में घुमते हुए देखा तो उसको रूकने का इशारा किया। पुलिस को देख वह भाग खडा हुआ। पुलिस ने पीछा कर उसको थोडी दूरी पर ही दबोच लिया। तलाशी लेने पर पुलिस ने उसके कब्जे से 53 पव्वे शराब के बरामद कर लिये। पूछताछ में उसने अपना नाम उमेश कुमार पुत्रबालचंन्द निवासी कुमारवाडा ऋषिकेश बताया। वहीं ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने गोविन्द नगर से एक युवक को 28 पव्वे शराब के साथ गिरफ्तार किया। जिसने अपना नाम हैप्पी पा राजेश जाटव निवासी गोविन्द नगर झुग्गी झोपडी बताया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

डीएवी पीजी कॉलेज छात्रा संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई ने जताया विरोध

संवाददाता

देहरादून। डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय पहुंच मिठाई बांट एसएसपी को पुष्प गुच्छ भेंट किये।

आज यहां डीएवी (पीजी) कॉलेज देहरादून के छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा एसएसपी कार्यालय में एक अनोखा विरोध एवं सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि छात्र संघ चुनाव के दौरान प्रशासन एवं पुलिस की भूमिका से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को चुनावी लाभ मिला तथा एवीबीपी प्रत्याशी को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसी के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एसएसपी देहरादून के गैरमौजूदगी में एसएसपी कार्यालय में उपस्थित पुलिस को प्रतीकात्मक रूप से मिठाई खिलाकर "आभार एवं सम्मान" व्यक्त किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि छात्र संघ चुनाव छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया से जुड़े होते हैं। संगठन ने चुनाव प्रक्रिया में प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच एवं पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनका यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। एनएसयूआई ने स्पष्ट किया कि छात्र हितों, निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश सचिव विनीत प्रसाद भट्ट, नगर निगम पार्षद रोबिन त्यागी एवं आयुष गुप्ता, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष डीएवी पीजी कॉलेज सिद्धार्थ अग्रवाल, जिलाउपाध्यक्ष युवा कांग्रेस प्रियांशु गौड़, छात्रनेता सौरभ सेमवाल सहित कई एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

भव्य रामलीला महोत्सव 2026' की स्मारिका का विमोचन

हमारे संवाददाता

देहरादून। श्री रामकृष्ण लीला समिति टिहरी 1952, देहरादून (पंजी.) द्वारा पुरानी टिहरी की 1952 से चली आ रही ऐतिहासिक रामलीला की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आयोजित होने जा रहे 'भव्य रामलीला महोत्सव 2026' की स्मारिका पुस्तिका का विमोचन किया गया। यह स्मारिका उत्तराखंड की

❑एक करोड़ से अधिक दर्शकों तक पहुंचेगी ऐतिहासिक रामलीलाः थापर



ऐतिहासिक धरोहर, पुरानी टिहरी की रामलीला की 1952 से अब तक की यात्रा तथा इसके गौरवशाली इतिहास और वर्तमान उपलब्धियों को समर्पित है।

इस अवसर पर रामलीला समिति के संरक्षक मंडल के सदस्य एवं वर्ष 1961 से रामलीला के वरिष्ठतम कलाकार श्री बछेंद्र कुमार पांडेय ने स्मारिका का विमोचन किया। समिति के अध्यक्ष अभिनव थापर ने कहा कि पुरानी टिहरी, जो गढ़वाल की ऐतिहासिक राजधानी रही है, की 1952 से चली आ रही प्राचीन रामलीला टिहरी बांध के निर्माण के बाद पुरानी टिहरी के जलमग्न होने से अपनी मूल भूमि से दूर हो गई थी। इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रखने और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने के संकल्प के साथ समिति ने वर्ष 2023 में 21 वर्षों के अंतराल के बाद देहरादून में इसका पुनर्जीवन किया। वर्ष 2025 में आयोजित भव्य रामलीला को विभिन्न देशों में डिजिटल माध्यमों से 82 लाख से अधिक दर्शकों ने देखा, जिसके चलते यह उत्तराखंड की सबसे अधिक देखी जाने वाली रामलीला बनी। इसी उपलब्धि को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष आधुनिक डिजिटल तकनीक के माध्यम से एक करोड़ से अधिक दर्शकों तक रामलीला पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष विशेष आकर्षण के रूप में उत्तराखंड की माटी से जुड़ा प्रसिद्ध 'पंचतत्त्व बैंड' भी रामलीला महोत्सव में अपनी शानदार संगीतमय प्रस्तुति देगा। बताया कि इस वर्ष रामलीला महोत्सव में संस्कृति और आधुनिक तकनीक का विशेष संगम देखने को मिलेगा। विशेष आकर्षण के रूप में लेजर एवं साउंड शो प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके माध्यम से गढ़वाल के गौरवशाली इतिहास को भव्य रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। समिति के संरक्षक बछेंद्र कुमार पांडेय ने कहा कि 'भव्य रामलीला महोत्सव 2026' की स्मारिका अतीत के गौरवशाली इतिहास और वर्तमान की उपलब्धियों का अनूठा संगम है।

इस वर्ष रामलीला मंचन के साथ भव्य मेले, भजन संध्या एवं उत्तराखंड के पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष अभिनव थापर, सचिव अमित पंत, संस्क्षक बछेंद्र कुमार पांडेय, नरेश कुमार, सह-सचिव गिरीश पैन्यूली, सहित कई लोग मौजूद रहे।

मां नंदा देवी सिद्धपीठ में 11 से 20 अक्टूबर तक होगा नवरात्रि पूजन

संवाददाता

देहरादून। मां नंदा देवी सिद्धपीठ में 11 अक्टूबर से नवरात्रि पूजन विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जायेगा।

आज यहां परेड ग्राउंड स्थित एक क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए श्री नंदादेवी बडी जात आयोजन समिति के अध्यक्ष हरेन्द्र सिंह रावत ने बताया कि शरदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर मां नंदा देवी सिद्धपीठ मंदिर नंदाधाम कुरूड में 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक विशेष पूजा अर्चना एवं नवरात्र पूजन



सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर विजयदशमी के पावन पर्व पर मां के प्रसाद एवं भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर बडीजात 2026 में प्रतिभाग करने वाले समस्त देव डोलियां, छतोलियां, निशान, चॉसिग्या खाडू के स्वामी, व देश विदेश से आये समस्त श्रद्धालुओं का सपरिवार सिद्धपीठ नंदाधाम कुरूड में माता का प्रसाद व आर्शीवाद ग्रहण करेंगे। आयोजन समिति ने यात्रा से पूर्व उत्पन्न 2026 व 2027 की असमंजस की स्थितियों को दरकिनार कर उत्तराखण्ड की अधिष्ठानी देवी मां नंदा की 12 वर्षीय ' श्री नंदा देवी बडी जात 2026 के सफल एवं ऐतिहासिक आयोजन समस्त श्रद्धालुओ के सराहनीय सहयोग से सकुशल सम्पन्न हो पाया है।

दिव्यांगजनों ने किया मुख्यमंत्री आवास कूच

संवाददाता

देहरादून। दिव्यांगजनों को मिलने वाली मदद को तीन हजार किये जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर दिव्यांगजनों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। जिनको रोक दिया गया। जिसके बाद जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया।



आज यहां काफी संख्या में दिव्यांगजन परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए। जहां से उन्होंने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। जब वह हाथीबडकला चौकी के पास पहुंचे तो पुलिस ने बैरकेडिंग लगाकर उनको रोक दिया। जिसके बाद वह वहीं धरने पर बैठ गये। धरने के दौरान उन्होंने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में दिव्यागों को मिलने वाली फाईनेशियल मदद को 1500 से बढाकर तीन हजार रूपये प्रतिमाह किया जाये। उन्होंने कहा कि रहने सहने और खर्च और जरूरी खाने के खर्च के हिसाब से समय-समय पर मदद का रिव्यू किया जाये। इसके साथ ही बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग लोगों पर खास ध्यान दिया जाये। उन्होंने कहा कि यह भी पक्का करें कि योग्य बेनिफिशियरी को रेगुलर और बिना किसी देरक के मदद दी जाये। उन्होंने कहा कि कई स्टूडेंटस को हायर एजुकेशन करते समय कम्युनिकेशन अकोमोडेशन और एक्सोसिबिलिटी में दिक्कतों का सामना करना पड सकता है। इसलिए उत्तराखण्ड सरकार से मांग करते हैं कि राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट और लागू सरकारी नियमों के अनुसार मांगों पर विचार किया जाये। उन्होंने कहा कि देहरादून में बाहर से एडमिशन, परीक्षा, ट्रेनिंग या पढाई के लिए आने वाले बधिर स्टूडेन्टस के लिए एक आसान सरकारी गेस्ट हाउस या फिर कोई सही टेम्पररी रहने की जगह देने की सम्भाना की जांच की जाये। उन्होंने कहा कि एडमिशन, पढने, सीखने और परीक्षाओं में बधिर, कम सुनने वाले स्टूडेंटस के लिए सही रहने की जगह और जरूरी सपोर्ट पक्का करें तथा सरकारी और सरकारी मदद वाले हायर एजुकेशनल इंस्टीटयूशज में बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए लागू पांच प्रतिशत रिजर्वेशन को पक्का किया जाये। उन्होंने कहा कि यह पक्का करें कि योग्य बेनिफिशियरी को रेगुलर और बिना किसी देरी के मदद दी जाये।

यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर विशेषज्ञ डॉक्टर नदारद

उत्तरकाशी(आरएनएस)। यमुनोत्री धाम के मार्ग की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े उठाए गए हैं। चारधाम यात्रा नोडल अधिकारी स्वास्थ्य डॉ. रमेश आर्य के शनिवार को किए गए निरीक्षण में महानिदेशालय स्तर से तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों के ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने का मामला सामने आया। बड़कोट और जानकीचट्टी में फिजिशियन एवं ऑर्थोपेडिक चिकित्सकों की तैनाती की गई थी लेकिन निरीक्षण के दौरान संबंधित डॉक्टर अपनी ड्यटी पर नहीं मिले। इसके अलावा बाहर से तैनात किए जाने वाले मेडिकल ऑफिसर और फार्मेसी ऑफिसर के भी उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई।नोडल अधिकारी ने यमुनोत्री यात्रा मार्ग के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बढ़ती तीर्थयात्रा को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बड़कोट अस्पताल में डॉ. अंगद राणा, खराड़ी में डॉ. अनुष्का गुलेरिया, राना में डॉ. पवन कठैत और जानकीचट्टी में डॉ. अखिल राणा यात्रियों को स्वास्थ्य सेवाएं देते मिले।यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने 23 सितंबर को स्वास्थ्य सचिव को पत्र भेजकर यात्रा के तहत तैनात फिजिशियन और ऑर्थोपेडिक चिकित्सकों के ड्यूटी से नदारद रहने का मामला उठाया था। अब नोडल अधिकारी के निरीक्षण में भी विशेषज्ञ चिकित्सकों के ड्यूटी ज्वाइन न करने की जानकारी सामने आने से तैनाती और मॉनिटरिंग व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।

सब्र ने जवाब दिया तो गैंती-फावड़े लेकर सड़क पर उतरे क्षेत्रवासी

कोटद्वार(आरएनएस)। लालढांग-चिल्लरखाल एलिवेटेड मार्ग निर्माण की मांग को लेकर जारी धरना-प्रदर्शन में शामिल क्षेत्रवासियों का सब्र जवाब दे गया। प्रदर्शनकारियों ने मांग को अनसुना करने पर रोष व्यक्त करते हुए खुद ही श्रमदान कर पुश्ता बनाया और मार्ग को समतल किया। संघर्ष समिति के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग और सामाजिक संगठनों के सदस्य गैंती, फावड़ा, बेलचा और तसला लेकर पहुंचे। सिगड्डी स्रोत नदी पर निर्माण कार्य शुरू करने से पहले भूमिया देवता की पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद जयकारों के साथ कार सेवा शुरू हुई। आंदोलनकारियों ने पत्थरों की चिनाई कर पुश्ता बनाया और मार्ग को समतल किया। कई स्थानों पर गड्ढे भरकर आम लोगों के आवागमन के लिए रास्ता खोला गया।समिति अध्यक्ष देवेंद्र रावत ने कहा कि 26 साल बाद भी सरकार कोटद्वार, लालढांग और गढ़वाल के करीब आठ लाख लोगों को सुगम आवागमन के लिए सड़क उपलब्ध नहीं करा पाई है। वन्यजीव संरक्षण और जनहित के लिए एलिवेटेड मार्ग ही स्थायी विकल्प है। संयोजक रविंद्र सौंद ने वन भूमि को नियमों के तहत डिनोटिफाई कर लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने और पर्याप्त बजट जारी कर निर्माण शुरू कराने की मांग की।

सू- दोकू क्र. 64

	2		6		8		3	
9		8		3		4		
							5	
5		2			7		6	
	8		4			1		3
				9				
8			9				1	
	5			1		6		2
		1	7				4	

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र. 63 का हल

2	6	3	8	1	4	9	7	5
9	5	4	2	6	7	3	1	8
8	7	1	9	3	5		6	2
6	2	7	5	4	8	4	3	9
3	9	8	6	7	1	2	5	4
4	1	5	3	2	9	6	8	7
5	3	2	4	8	6	7	9	1
1	8	6	7	9	2	5	4	3
7	4	9	1	5	3	8	2	6

भाजपा का 'वार' विपक्ष 'लाचार'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड की सियासत में 2027 का चुनावी रण अभी दूर है, लेकिन भाजपा ने अपनी रणनीति का खाका खींचना शुरू कर दिया है। 70 विधानसभा सीटों वाली बिसात पर भाजपा की नजर 60 सीटों पर है। पार्टी ने इन सीटों को केंद्र में रखकर संगठन को सक्रिय करने, कमजोर कड़ियों को दुरुस्त करने और बूथ स्तर तक चुनावी तैयारी को धार देने की कवायद शुरू कर दी है। भाजपा के 60 पार लक्ष्य ने विपक्ष के सामने भी चुनौती खड़ी कर दी है। कांग्रेस के लिए मामला अब सिर्फ अपनी सीटें बढ़ाने का नहीं, बल्कि भाजपा को उसके घोषित लक्ष्य तक पहुंचने से रोकने की राजनीतिक लड़ाई का भी है। वहीं बची हुई सीटों पर निर्दलीय, क्षेत्रीय दल और छोटे राजनीतिक समूह अपने लिए जगह तलाशेंगे।

भाजपा की खासियत उसका संगठनात्मक ढांचा है और इस बार भी पार्टी चुनावी तैयारी को अंतिम दौर तक टालने के मूड में नहीं दिख रही। बूथ, शक्ति केंद्र और मंडल स्तर पर गतिविधियों को तेज करने के साथ उन सीटों पर विशेष फोकस किया जा रहा है जहां पार्टी को अतिरिक्त मेहनत की जरूरत महसूस होती है। 60 पार का लक्ष्य अपने आप में बड़ा राजनीतिक संदेश है। इसका अर्थ है कि भाजपा केवल अपनी मजबूत सीटों पर निर्भर रहने के बजाय प्रदेश के लगभग हर हिस्से में मुकाबला खड़ा करने की तैयारी में है। यानी भाजपा की लड़ाई सिर्फ सत्ता बचाने की नहीं, अपने चुनावी दायरे को अधिकतम करने की है।

भाजपा ने यदि 60 सीटों को लक्ष्य बनाया है तो कांग्रेस के सामने राजनीतिक चुनौती साफ है। उसे एक तरफ अपने मजबूत क्षेत्रों को बचाना होगा, दूसरी तरफ उन सीटों पर वापसी की कोशिश करनी होगी जहां पिछली बार पार्टी कमजोर रही। लेकिन कांग्रेस की राह में संगठनात्मक समन्वय और नेतृत्व के सवाल भी हैं। वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता, उनके बीच तालमेल, टिकट की दावेदारी और स्थानीय गुटबाजी जैसे मुद्दे चुनावी रणनीति पर असर डाल सकते हैं। कांग्रेस के लिए सबसे अहम सवाल यह होगा कि क्या वह भाजपा के व्यापक संगठनात्मक अभियान के मुकाबले समय रहते अपना चुनावी नेटवर्क उसी स्तर तक सक्रिय कर पाती है।

भाजपा ने 60 सीटों को अपने फोकस में रखा है तो बाकी 10 सीटें राजनीतिक रूप से खास दिलचस्प हो सकती हैं। यहां कांग्रेस के साथ-साथ निर्दलीय और छोटे दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। उत्तराखंड में स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़ कई बार दलगत समीकरणों को प्रभावित करती रही है। ऐसे



◆भाजपा ने कसी कमर, 60 सीटों को फोकस में रखकर मैदान सजाने की कवायद
◆बाकी 10 सीटों पर कांग्रेस, निर्दलीय और छोटे दलों के बीच जमीन बचाने की जंग
◆2027 के लिए भाजपा का बड़ा दांव, कांग्रेस के सामने अस्तित्व बचाने की चुनौती

में कुछ सीटों पर मुकाबला सीधे भाजपा बनाम कांग्रेस तक सीमित रहने के बजाय बहुकोणीय हो सकता है। छोटे दलों के सामने चुनौती यह है कि वह अपने मुद्दों को चुनावी विमर्श में कितना स्थान दिला पाते हैं। निर्दलीयों के लिए चुनौती अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक जमीन को वोट में बदलने की होगी।

भाजपा के लिए 60 सीटों का लक्ष्य घोषित करना आसान है, लेकिन उसे जमीन पर साधना अलग चुनौती है। 70 में से 60 सीटों पर प्रभावी मुकाबले की तैयारी का मतलब है कि पार्टी को लगभग हर क्षेत्र में संगठन, उम्मीदवार और स्थानीय समीकरणों पर बारीकी से काम करना होगा, जहां पार्टी मजबूत है, वहां प्रदर्शन कायम रखना होगा। जहां कमजोर है, वहां सेंध लगाने की रणनीति बनानी होगी और जहां स्थानीय असंतोष या बहुकोणीय मुकाबला है, वहां टिकट चयन सबसे महत्वपूर्ण हथियार बन सकता है। यहीं से भाजपा की असली परीक्षा शुरू होगी।

जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, 60 सीटों का फोकस टिकट के दावेदारों की संख्या भी बढ़ा सकता है। हर विधानसभा में पार्टी के भीतर कई संभावित चेहरे सक्रिय होंगे। ऐसे में संगठन के लिए सबसे बड़ी चुनौती केवल मजबूत उम्मीदवार तलाशना नहीं, बल्कि टिकट कटने या दावेदारी कमजोर पड़ने की स्थिति में संभावित असंतोष को संभालना भी होगी। कांग्रेस में भी यही स्थिति रहने वाली है। दोनों दलों में टिकट वितरण के दौरान स्थानीय समीकरण, गुटीय संतुलन और जीत की रणनीति के बीच तालमेल बैठाना अहम होगा।

भाजपा के 60 पार अभियान का जवाब केवल सरकार विरोधी मुद्दे गिनाने से नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को यह तय करना होगा कि वे किन सीटों पर अपना पूरा राजनीतिक जोर लगाएंगे और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। रोजगार, पलायन, भू-कानून, महंगाई, स्थानीय विकास, पहाड़ और मैदान का संतुलन जैसे मुद्दे चुनावी बहस का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन इन मुद्दों को वोट में बदलने के लिए विपक्ष को संगठनात्मक तैयारी और स्थानीय नेतृत्व की जरूरत होगी। उत्तराखंड की 70 सीटों पर चुनावी युद्ध अभी औपचारिक रूप से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक सेनाएं अपनी-अपनी तैनाती शुरू कर चुकी हैं। भाजपा ने 60 सीटों का लक्ष्य सामने रखकर मैदान की घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस के सामने इस घेराबंदी को तोड़ने की चुनौती है, जबकि छोटे दल और निर्दलीय अपने प्रभाव वाले इलाकों में राजनीतिक जगह बचाने की कोशिश करेंगे। आने वाले महीनों में उम्मीदवारों की सक्रियता, टिकट की दावेदारी, संगठनात्मक फेरबदल और स्थानीय समीकरण इस तस्वीर को और बदलेंगे। 70 सीटों का चुनाव है, लेकिन भाजपा ने फिलहाल अपनी नजर 60 पर गड़ा दी है। अब सवाल यह नहीं कि भाजपा कितनी सीटें जीतेगी। यह भविष्यवाणी होगी कि सवाल यह है कि कांग्रेस और बाकी दल भाजपा की इस 60 सीटों वाली चुनावी घेराबंदी का जवाब किस रणनीति से देते हैं।

छात्र संघ चुनाव के बाद से मेयर और विधायक के बीच गहराए मतभेद

हल्द्वानी(आरएनएस)। डिग्री कॉलेज हल्द्वानी छात्र संघ चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। सोशल मीडिया में इसकी खूब चर्चा हो रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) समर्थित प्रत्याशी धीरज बिष्ट की हार और बागी प्रत्याशी आर्यन बेलवाल की जीत ने क्षेत्र के दो बड़े भाजपा नेताओं मेयर गजराज सिंह बिष्ट और कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत के बीच के मतभेदों को सार्वजनिक कर दिया है। इस चुनाव में एबीवीपी से जुड़े कई पूर्व छात्र संघ पदाधिकारी खुलकर बागी प्रत्याशी आर्यन बेलवाल के समर्थन में आ गए थे, जिससे संगठन की कमजोरी उजागर हुई। दरअसल मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्च पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने रोष जताते हुए कहा कि एबीवीपी के छात्रों को पुलिस की लाठियां झेलनी पड़ीं। मेयर ने इस दौरान कांग्रेस राज में भी छात्रों का ऐसा उत्पीड़न नहीं हुआ था। दिवंगत नेता स्व. इंदिरा हृदयेश की तारीफ करते हुए कहा कि वे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को भी पूरा सम्मान देती थीं।

एक तरफ जहां मेयर प्रशासन और अपनों के भीतरघात से नाराज दिखे, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत बागी प्रत्याशी आर्यन बेलवाल के समर्थन में दिखते नजर आए। उन्होंने कहा कि जो जीत गया है वह सर्वमान्य विजयी घोषित हो गया है। मतपत्र काउंटिंग के दौरान मत पत्र फाड़ने की घटना को पूरी तरह से गलत बताया। विधायक बंशीधर भगत ने बिना नाम लिए कहा कि जो नेता कांग्रेस नेताओं की तारीफ कर रहे हैं उनको शायद कांग्रेस राज की सही स्थिति का अंदाजा नहीं है। वहीं, इस पूरे घटनाक्रम के बीच भाजपा प्रवक्ता विकास भगत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की है, जिसमें उन्होंने निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को प्रशासन की जमकर तारीफ की है।

इस छात्र संघ चुनाव ने मेयर और विधायक के बीच जल रही राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में घी डालने का काम किया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कालाढूंगी विधानसभा सीट की दावेदारी को लेकर विधायक बंशीधर भगत और मेयर गजराज सिंह बिष्ट के बीच लंबे समय से अनबन चल रही है। अब छात्र संघ चुनाव के बहाने दोनों गुटों का आमने-सामने आना यह साफ संकेत देता है कि आने वाले समय में जिले की भाजपा राजनीति में और खींचतान हो सकती है।



दिनेश आर्य ने राज्यसभा सीट पर नामांकन दाखिल किया

संवाददाता

देहरादून। दिनेश आर्य ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में राज्यसभा सीट पर नामांकन दाखिल किया। आज यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा, देहरादून में राज्यसभा सीट के लिए प्रत्याशी दिनेश आर्य के नामांकन के अवसर पर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने दिनेश आर्य को नामांकन के अवसर पर शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट सहित मंत्रीगण, सांसद एवं विधायक उपस्थित रहे।

कैंचीधाम के पास खाई में गिरी पिकअप, तीन लोग घायल

हमारे संवाददाता

नैनीताल। आज सुबह आपदा कंट्रोल रूम नैनीताल से एसडीआरएफ पोस्ट खैरना को कैंचीधाम के पास पिकअप वाहन के खाई में गिरने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर जिला पुलिस बल के साथ एसडीआरएफ टीम द्वारा संयुक्त रूप से रेस्क्यू कार्य किया गया। एसडीआरएफ टीम के पहुंचने से पूर्व स्थानीय लोगों द्वारा वाहन में सवार तीनों घायलों को खाई से बाहर निकाल लिया गया था। एसडीआरएफ टीम द्वारा तीनों घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल भिजवाया गया तथा घटनास्थल पर सर्चिंग की गई। दुर्घटनाग्रस्त पिकअप लालकुआं से दूध लेकर जा रहा था, जो रात्रि लगभग 2 बजे कैंचीधाम मंदिर के पास खाई में गिर गया था। घायलों में अंकित सिंह (33 वर्ष), बॉबी तथा मोहम्मद साकिब (10 वर्ष) शामिल है।

कांग्रेस के 'आंतरिक लोकतंत्र' पर...

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

है। पांच अक्टूबर को नैनीताल और ऊधमसिंह नगर क्षेत्र में यात्रा के दौरान कई विधायक और पूर्व विधायक भी शामिल हुए। इससे पार्टी के भीतर अलग-अलग नेताओं के बीच राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हुई हैं। यही वजह है कि भाजपा इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस की गुटबाजी से जोड़ रही है। कांग्रेस के लिए चुनौती यह है कि चुनावी अभियान के दौरान वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता को संगठन की सामूहिक रणनीति के साथ कैसे जोड़ा जाए। दूसरी ओर भाजपा के लिए यह घटनाक्रम कांग्रेस के खिलाफ संगठनात्मक एकजुटता का सवाल उठाने का राजनीतिक अवसर बन गया है। अब यह मामला केवल प्रदेश कांग्रेस के भीतर की नाराजगी नहीं रह गया है। हरीश रावत को दिल्ली बुलाया गया है और पार्टी नेतृत्व उनका पक्ष सुनने के बाद आगे का निर्णय करेगा। कांग्रेस की ओर से संकेत दिया गया है कि चुनावी अभियान सामूहिक नेतृत्व में आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि रावत की यात्रा को लेकर कांग्रेस नेतृत्व और वरिष्ठ नेता किस तरह का रास्ता निकालते हैं। फिलहाल चिट्ठी ने यात्रा को रोका नहीं, बल्कि कांग्रेस के भीतर की बहस को सार्वजनिक कर दिया है और भाजपा ने उसी बहस को अपने राजनीतिक हमले का मुद्दा बना लिया है। लोकतंत्र बचाओ के राष्ट्रीय अभियान के बीच आंतरिक लोकतंत्र का सवाल। यही वह राजनीतिक विरोधाभास है, जिसे भाजपा उत्तराखंड के चुनावी विमर्श में जोर-शोर से उठाने की तैयारी में दिखाई दे रही है।

चिट्ठी, यात्रा और बवाल

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

सामने चुनौती केवल एक यात्रा को लेकर निर्णय लेने की नहीं, बल्कि उत्तराखंड में चुनाव से पहले संगठनात्मक समन्वय बनाए रखने की भी है। कांग्रेस के भीतर चल रहा यह विवाद भाजपा के लिए भी राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। चुनावी राजनीति में विपक्ष के संगठनात्मक मतभेद सत्ता पक्ष के लिए हमले का आधार बनते हैं। कांग्रेस जितना अपने भीतर के विवाद को सार्वजनिक रूप से संभालने में व्यस्त होगी, उतना ही भाजपा उसके नेतृत्व और एकजुटता पर सवाल उठा सकती है। हालांकि कांग्रेस के सामने इसका दूसरा पहलू भी है। यदि पार्टी इस विवाद को संवाद के जरिए सुलझा लेती है और वरिष्ठ नेताओं को एक साझा चुनावी मंच पर ले आती है, तो मौजूदा टकराव को संगठनात्मक समन्वय में बदला जा सकता है। फिलहाल मामला खुला है और अगले कुछ दिनों में होने वाली बैठकों तथा नेतृत्व के फैसले पर निगाह रहेगी। दरअसल, उत्तराखंड कांग्रेस में इस समय चिट्ठी केवल एक पत्र नहीं है, यात्रा केवल एक कार्यक्रम नहीं है और बवाल केवल नेताओं की नाराजगी तक सीमित नहीं है। इसके पीछे चुनाव से पहले संगठन की कमान, राजनीतिक भूमिका और अभियान की दिशा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस इस विवाद को सार्वजनिक टकराव बनने से रोकती है या यह चिट्ठी आने वाले चुनावी अभियान की पटकथा का एक बड़ा अध्याय बन जाती है।

उत्तराखण्ड राज्य बने 26 साल हो गए हैं, इन 26 सालों में गंगोत्री विधानसभा वासियों को क्या मिला ?

लोकेंद्र सिंह बिष्ट

उत्तरकाशी। चलो आज बात करतें है गंगोत्री विधानसभा के रामलीला मैदान/आजाद मैदान की। रामलीला मैदान यानी आजाद मैदान। उत्तरकाशी का दिल (हार्ट ऑफ द सिटी) जिसके लिए समूचे उत्तरकाशी वासियों का दिल धड़कता है। कभी बाड़ाहाट के थौलू के लिए तो कभी रामलीला के लिए, कभी फुटबॉल के लिए धड़कता था, तो कभी क्रिकेट के लिए, कभी रैलियां के लिए तो कभी खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिय, तो कभी कभार मदारियों के नटखट के लिए और सबसे ज्यादा 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड के लिए।

आज उत्तरकाशी का दिल बैठ रखा है, हार्ट ऑफ द सिटी आज खामोश है। इस रामलीला मैदान का चक्कर लगाओ तो एक इंच भूमि खाली नहीं मिलेगी। कभी लगता है ये पार्किंग प्लेस है, कभी लगता है ये सब्जी मंडी है, कभी लगता है ये फल मंडी है। नहीं ये तो रेहड़ी ठेली और जूस वालों की जगह है। कभी लगता है ये तो बंजारों की टैंट बस्ती है,, कभी लगता है ये तो बड़े बड़े ट्रकों,गाड़ियों का वर्कशॉप है। चारों तरफ नजर दौड़ाओ तो लगता है ये तो मात्र कीचड़ का मैदान भर रह गया है।



आखिर रामलीला मैदान है किसका? कभी जिला पंचायत वाले मेला लगाकर करोड़ों डकार जाते जाते हैं। कभी नगरपालिका वाले ठेली रेडी, सब्जी, फल, जूस, गन्ने, पटाखे देखने लगाकर। तो कभी रामलीला, तो रैलियां, कभी कथाएँ तो कभी संगीत। कभी फुटबॉल, कभी क्रिकेट। जेन जी यानी युवाओं के पास आज उत्तरकाशी में खेलने भर के लिए एकबड़ना सा मैदान तक नहीं है। सबका साथ, सबका विकास।

जिला पंचायत? नगरपालिका या फिर जिला प्रशासन? कोई तो नैतिक जिम्मेदारी लेनिया मैदान की। जब यात्रकाल में ये पार्किंग के लिए खोला जाता है तो यहां वर्कशॉप क्यों चल रही हैं? एक नहीं कई कई वर्कशॉप। जहां देखो बड़े बड़े ट्रकों को ठोका पीटा जा रहा है।

चारों तरफ नजर दौड़ाओ तो कीचड़ ही कीचड़ का राज। जिन्होंने इसे यात्रकाल में पार्किंग के लिए अनुमति दी तो ठीक है लेकिन इसको वर्कशॉप किसने बना दिया? ठेली रेवड़ी वाले कहां से आये? सब्जी मंडी, फल मंडी, गन्ने के जूस की मंडी कैसे बन गया अपना रामलीला मैदान? ये बंजारे किसने बसा दिये। मुझे याद है कि रामलीला मैदान के रखरखाव पर करोड़ों डकार गए लेकिन किसी ने डकार तक नहीं ली। किसी ने इसकी छाती पर रेत बिछाई तो किसी ने मिट्टी उड़ेली, किसी ने घास दूब लगाई लेकिन किसी ने डकार तक नहीं ली। यहां तक मरे जानवर भी दफनाए गए।

(बीजेपी दावेदार, गंगोत्री विधानसभा)

स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 53 छात्राओं ने किया रक्तदान!

संवाददाता

देहरादून। सेवा, संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल पेश करते हुए ओएनजीसी कौलागढ़ स्थित बीएस नेगी महिला प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थान की छात्राओं ने रक्तदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय पहल की। रणजीत सिंह वर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 53 छात्राओं ने एक साथ रक्तदान कर 53 यूनिट रक्त दिया। ट्रस्ट के सचिव एवं कार्यक्रम आयोजक मोहन सिंह खत्री ने कहा कि देहरादून में पहली बार एक साथ 53 छात्राओं द्वारा रक्तदान किया जाना अपने आप में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है।



किसी जरूरतमंद मरीज के लिए रक्त की एक-एक बूंद अनमोल होती है। स्वस्थ लोगों को नियमित रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए, ताकि आपात स्थिति में किसी मरीज को रक्त की कमी से जूझना न पड़े। ट्रस्ट अध्यक्ष अजय वर्मा ने छात्राओं के उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि रक्तदान केवल सामाजिक सेवा नहीं, बल्कि मानवता के प्रति जिम्मेदारी भी है। शिविर में संस्थान की प्रधानाचार्य नमिता ममगाई ने भी रक्तदान कर छात्राओं का उत्साह बढ़ाया। संस्थान की ओर से ट्रस्ट अध्यक्ष अजय वर्मा और सचिव मोहन सिंह खत्री को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन पूनम भंडारी ने किया।

विवेकानंद नेत्रालय में अत्याधुनिक जीस सायरस 6000 एंजियोप्लेक्स ओसीटी मशीन का लोकार्पण

संवाददाता

देहरादून। रामकृष्ण मिशन आश्रम, देहरादून स्थित विवेकानंद नेत्रालय में अत्याधुनिक जीस सायरस 6000 एंजियोप्लेक्स ओसीटी मशीन का लोकार्पण किया गया। यह मशीन एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन के सहयोग से उपलब्ध कराई गई है।



कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक एस. पी. पंत रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में वी. के. थापलियाल एवं वी. पी. जोशी उपस्थित रहे। इस अवसर पर रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी असीमात्मानंद महाराज सहित चिकित्सक एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

नई मशीन में ओसीटी (ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी) और ओसीटी एंजियोग्राफी (ओसीटीए) जैसी आधुनिक तकनीक उपलब्ध है। इसके माध्यम से रेटिना और आंखों की सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं की विस्तृत जांच की जा सकेगी। इससे रेटिना संबंधी रोगों की पहचान, निदान और निगरानी के साथ ही मरीजों के उपचार की बेहतर योजना बनाने में चिकित्सकों को मदद मिलेगी।

विवेकानंद नेत्रालय ने इस सहयोग के लिए एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक से युक्त यह सुविधा जरूरतमंद मरीजों को गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती नेत्र चिकित्सा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

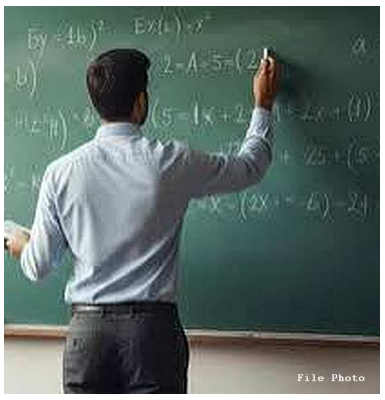
नेत्रालय ने कहा कि सेवा ही साधना है की भावना के साथ आधुनिक चिकित्सा तकनीक को जनसेवा से जोड़ने का प्रयास निरंतर जारी रहेगा।

फर्जी यूटीईटी से नौकरी पर 3 शिक्षक बर्खास्त

हमारे संवाददाता

अल्मोड़ा। फर्जी यूटीईटी प्रमाणपत्र के आधार पर प्राथमिक शिक्षक की नौकरी हासिल करने का मामले में हुई जांच में प्रमाणपत्र फर्जी पाए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने तीन सहायक अध्यापकों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। विभाग ने तीनों के खिलाफ पुलिस में भी तहरीर दी है।

अल्मोड़ा के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय की ओर से 7 नवंबर 2025 को सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भैंसियाछाना ब्लॉक के तीन अभ्यर्थियों को 27 जनवरी 2026 को अलग-अलग विद्यालयों में नियुक्ति दी गई। इनमें भूपेंद्र कुमार को राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुनखेत नवीन, अंजना ग्वासिकोटी को राजकीय प्राथमिक विद्यालय बौड़ा और प्रियांशु चंद्र को राजकीय प्राथमिक विद्यालय बूढ़ाधौर में तैनाती मिली थी। नियुक्ति के लिए तीनों ने आवेदन के साथ उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूटीईटी प्रथम वर्ष 2024 के प्रमाणपत्र लगाए थे। प्रमाणपत्रों को लेकर शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने संबंधित दस्तावेजों



को जांच के लिए उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर भेजा। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर ने 6 जुलाई 2026 को अपनी जांच रिपोर्ट विभाग को सौंपी। रिपोर्ट में सामने आया कि तीनों अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों पर दर्ज अनुक्रमांक परिषद की ओर से जारी ही नहीं किए गए थे। जांच में परिषद के मूल टेबुलेशन रजिस्टर में भी तीनों अभ्यर्थियों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला।

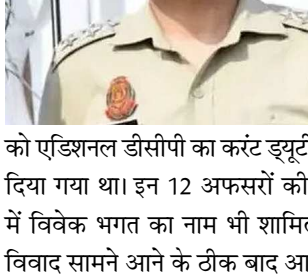
इसके अलावा प्रमाणपत्र और अंकपत्र पर दर्ज क्यूआर कोड भी जांच में फर्जी पाए गए। इसके बाद विभागीय जांच समिति ने 14 जुलाई 2026 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति हासिल करने की बात सामने आने के बाद तीनों शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद तीनों शिक्षक अपने बचाव में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। उन्होंने पारिवारिक परिस्थितियों और बीमारी का हवाला देते हुए त्यागपत्र देने और उसे स्वीकार करने का अनुरोध किया। हालांकि, फर्जी दस्तावेजों से जुड़ी विभागीय जांच जारी होने के कारण अधिकारियों ने उनके त्यागपत्र स्वीकार नहीं किए। जांच पूरी होने के बाद शिक्षा विभाग ने तीनों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दीं। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा डॉ. रवि मेहता के अनुसार, दस्तावेजों की जांच में तीनों शिक्षकों के प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए। उन्होंने बताया कि मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों और पुलिस को भी तहरीर दी गई है। अल्मोड़ा कोतवाली के प्रभारी योगेश उपाध्याय ने बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से तीन शिक्षकों के खिलाफ फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने के मामले में तहरीर मिली है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यूट्यूबर यूके 07 राइडर अनुराग डोभाल गिरफ्तार

हमारे संवाददाता

देहरादून। बिग बॉस फेम और चर्चित यूट्यूबर यूके 07 राइडर अनुराग डोभाल एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। पुलिस ने मारपीट, धमकी और जान से मारने की कोशिश के आरोप में अनुराग डोभाल को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को आज सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा।

मामला अनुराग डोभाल के रिश्तेदार राज सिंह चौहान की शिकायत से जुड़ा है। राज सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में अनुराग डोभाल और उनके साथियों



पर मारपीट करने, जान से मारने की कोशिश करने और धमकी देने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के आधार पर नेहरू कॉलोनी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत के मुताबिक, 5 अक्टूबर की शाम करीब छह बजे अनुराग डोभाल कुछ युवकों के साथ राज सिंह से मिलने पहुंचे थे। राज सिंह के मुताबिक, वह उस समय एक कार कंपनी के शोरूम में काम में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने बाद में मिलने की बात कही। इसके बाद रात करीब आठ बजे वह एक कैफे पहुंचे, जहां अनुराग डोभाल और उनके कुछ साथी कार में मौजूद थे। राज सिंह का आरोप है कि बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया। उन्होंने पुलिस को बताया कि इसी दौरान अनुराग डोभाल ने उन्हें धमकाया और कथित तौर पर अपने प्रभाव का हवाला दिया। इसके बाद उनके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। शिकायतकर्ता के मुताबिक, उसका गला दबाने और मोबाइल फोन छीनने का प्रयास किया गया। आरोप है कि इसके बाद साथियों को उसे जान से मारने के लिए कहा गया। थाना नेहरू कॉलोनी प्रभारी देवेंद्र चौहान के मुताबिक, राज सिंह चौहान की शिकायत के आधार पर अनुराग डोभाल समेत अभय चौधरी, तपन पंडित, धवल राजपुरोहित, अभिषेक टाइगर, अभिनव श्रीवास्तव और गुरु भाई समेत अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार, मामले में अनुराग डोभाल समेत कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अनुराग डोभाल की गिरफ्तारी धारा 151 के तहत की गई है। अब पुलिस सभी गिरफ्तार आरोपियों को सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगी।

नाइजीरियाई वायुसेना का सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त, 32 लोगों की मौत

संवाददाता

नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिमी नाइजीरिया के ओंडो राज्य में नाइजीरियाई वायुसेना का एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस दर्दनाक हादसे में विमान में सवार 25 यात्रियों और 7 क्रू मेंबर्स समेत सभी 32 लोगों की मौत हो गई है। तटीय शहर इग्बोकोडा के पास विमान का मलबा बरामद हुआ। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनूबू ने हादसे में किसी के भी जीवित न बचने की पुष्टि करते हुए गहरा शोक व्यक्त किया है और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। नाइजीरिया के नागरिक उड्डयन मंत्री फेस्टस कियामो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वायुसेना का ATR-42 विमान बेनिन शहर से लागोस के लिए एक नियमित मिशन पर उड़ान भर रहा था। सोमवार सुबह अंतरराष्ट्रीय समयानुसार करीब 8:13 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल का विमान से संपर्क अचानक टूट गया। काफी मशक्कत के बाद तटीय शहर इग्बोकोडा के पास एक नौसैनिक अड्डे के समीप दलदली क्रीक वाले इलाके में विमान का मलबा बरामद हुआ नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला टिनूबू ने कहा कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने उन्हें घटना की पूरी जानकारी दे दी है। हादसे पर राष्ट्रपति ने बयान जारी कर कहा, मैंने नाइजीरियाई वायुसेना को इस भीषण हादसे के कारणों की तत्काल और गहन जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

सरकार ने रोका भगत का प्रमोशन!

संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (एसीपी) विवेक भगत फिलहाल अपने मौजूदा पद पर ही बने रहेंगे। दिल्ली में चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान महिला पत्रकार से कथित बदसलूकी के आरोपों के बीच उन्हें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (अतिरिक्त डीसीपी) का करंट ड्यूटी चार्ज देने के आदेश को टाल दिया गया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक ये फैसला खुद विवेक भगत की गुजारिश पर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि जब तक पूरे मामले की निष्पक्ष और संतोषजनक जांच पूरी नहीं हो जाती वे यह जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे।

हाल ही में दिल्ली सरकार ने 5 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया था, जिसमें डीएएनआईपीएस कैडर के 12 अफसरों



को एडिशनल डीसीपी का करंट ड्यूटी चार्ज दिया गया था। इन 12 अफसरों की सूची में विवेक भगत का नाम भी शामिल था। विवाद सामने आने के ठीक बाद आए इस आदेश को विपक्ष और सोशल मीडिया पर एक तरह से प्रमोशन के तौर पर देखा जा रहा था, जिसको लेकर सरकार पर सवाल खड़े होने लगे थे। हालांकि, सरकार ने स्थिति साफ करते हुए बताया कि 12 अधिकारियों को करंट ड्यूटी चार्ज देने का प्रस्ताव 25 अगस्त को ही तैयार कर लिया गया था यानी उस घटना से काफी पहले जिसको लेकर विवाद हुआ है। अब संशोधित आदेश जारी कर बाकी 11 अफसरों को तो नई जिम्मेदारी दे दी गई है, लेकिन विवेक भगत के चार्ज को फिलहाल होल्ड पर रख दिया गया है।

यह पूरा मामला मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में चल रहे एक विरोध प्रदर्शन के दौरान का है। आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात एसीपी विवेक भगत ने कवरेज कर रही एक महिला पत्रकार के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की थी। मामला तूल पकड़ने के बाद इसकी जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है।

चुनाव आयोग के दफ्तर के पास ही धरने पर बैठ गए

संवाददाता

नई दिल्ली। नए वोटर रजिस्ट्रेशन से जुड़े फॉर्म 6 में बदलाव के विवाद को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने मंगलवार को चुनाव आयोग के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन के मकर द्वार से चुनाव आयोग मुख्यालय तक निकाले जा रहे विपक्षी सांसदों के मार्च को पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। पुलिस द्वारा रास्ता रोके जाने पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सुरक्षा बैरिकेड पर चढ़कर तिरंगा लहराया। इसके बाद वह अन्य नेताओं के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर के पास ही धरने पर बैठ गए। मकर द्वार से शुरू हुआ मार्च जैसे ही आगे बढ़ा, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर नेताओं को रोक दिया। प्रदर्शन को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई थी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वज्र वाहन तैनात किए गए थे और ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जा रही थी।

इस बीच एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम यह रहा कि आम आदमी पार्टी ने इस पूरे विरोध प्रदर्शन से दूरी बनाए रखी और गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद पार्टी का कोई नेता मार्च में शामिल नहीं हुआ। फॉर्म 6 में बदलाव और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से भड़का विवाद विपक्ष के इस प्रदर्शन के केंद्र में चुनाव आयोग का वह फॉर्म 6 है, जिसका इस्तेमाल नए



वोटर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए किया जाता है। विपक्षी दलों का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के दौरान फॉर्म 6 में अपनी मर्जी से बदलाव किए हैं।

यह राजनीतिक विवाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद और गहरा गया। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि उसने फॉर्म 6 में किसी भी तरह के बदलाव को कोई मंजूरी नहीं दी है। इसी टिप्पणी को आधार बनाकर विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है। मार्च में शामिल विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म 6 के मामले में देश को गुमराह किया है। नेताओं के मुताबिक, उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर से जनता का भरोसा पूरी तरह उठ गया है, जिसके चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, *एडवोकेट*
बैजनाथ, *एडवोकेट*

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्री के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।